(छ) 1994-95 के दौरान गन्ने के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य 250 मिलियन मीट्री टन है। 1994-95 में गन्ने के उत्पादन में गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

(ज) गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य 1993-94 में 34.50 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1994-95 में 39.10 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए हैं जिसमें 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली की व्यवस्था है और उस स्तर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर आनुपातिक प्रीमियम दिए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न राज्यों में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत से विकासात्मक कार्यक्रम भी चला रही है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ने के लिए भुगतान किए गए मूल्य

(मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में)

राज्य	1991-92		1992-93		1993-94	
	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
आंध्र प्रदेश	31.52–40.59		35.56–48.65		39.37–56.33	
गुजरात	27.00–60.00		उ०न०–उ०न०		31.00–50.00	
कर्नाटक	30.89–45 00		29.36–50 00		45.00–65.00	
तमिल नाडु	31.00-44.40		36.35–55.11		36.35–55.11	
उत्तर प्रदेश	45.00–48.00		46.00–49.00		50.00–61.00	
महाराष्ट्र	29.00–52.50		31.00–49.65		36.00–61.00	

उ०न०=उपलब्ध नहीं।

Universalisation of Primary Education

*255. SHRI SOM PAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an intensive study has been conducted recently in certain States regarding universalisation of primary education in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what changes are proposed to be made by Government in the primary education system as a result thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c) As part of the preparatory exercises for District Primary Education Programme (DPEP), Baseline Studies were conducted in 46 districts spread over 8 States.

Studies reveal that the position of learning achievement is quite low in several of these districts. The findings of the study have helped to define better the relevant strategies for interventions under District Primary Education Programme like integrated pedagogy, teacher training and curriculum development based on multigrade teaching requirements, under the programme.

स्व-वित्त योजना–7 के अंतर्गत मकान

*256. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या शहरी विकास मंत्री 9 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 613 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व-वित्त योजना-7 के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए और कितने मकानों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को दुबारा बढ़ाया गया था ; यदि हाँ, तो किस तारीख तक और इसके क्या कारण थे; और

(ग) बढ़ाई गई अवधि के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई स्व-वित्त पोषित आवासीय स्कीम- VII के अन्तर्गत द्वारका और रोहिणी में लगभग 3200 स्व-वित्त पोषित स्कीम फ्लैट (श्रेणी–II) हेतु आवेदन पत्र मांगे थे।